भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 275
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायालयों में अवसरंचनात्मक ढांचे के विकास की योजना

275. श्री वि. विजयसाई रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसरंचनात्मक ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के तहत निधियों के बंटवारे के निर्धारित स्वरूप का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को उपर्युक्त योजनाओं के तहत दी गई वित्तीय और अन्य सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार के हाथों में है । राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए, संघ सरकार ने केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि हिस्सा बांटने की पद्धति में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध करने द्वारा न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रुप से प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया है । वर्तमान में 8 पूर्वोत्तर और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) के लिए निधि हिस्सा बाटने की पद्धति 90 :10 (केन्द्र; राज्य) है और शेष राज्यों के लिए 60:40 है । संघ-राज्यक्षेत्रों में 100 प्रतिशत सहायता दी गई है । सरकार ने उपर्युक्त योजना को, और पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए, 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 9000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ, बढ़ाया है जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा भी सम्मिलित है । इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारिओं के लिए न्यायालयी भवन और आवासीय परिसरों का निर्माण आता है । स्कीम में अब इसके अतिरिक्त जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कम्पूटर कक्षों और वकीलों के हालों का निर्माण भी सम्मिलित है । वर्ष 1993- 94 में स्कीम के प्रारंभ से केन्द्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षत्रों को स्कीम के अधीन 8758.70 करोड़ रुपये जारी किए हैँ । जिसमें से 199.92 करोड़ की राशि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई है । विगत पांच वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई निधि की वर्ष-वार प्रास्थिति निम्नानुसार हैं :

आंध्र प्रदेश

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
निधि जारी	0.00	0.00	10.00	20.00	10.28	0.00

*28.01.2022 तक

****